हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 74 | देहरादून, मंगलवार, 06 सितंबर, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

'सल्ट क्रान्ति' के शहीद दिवस कार्यक्रम में सीएम ने की कई घोषणाएं 3

भू कानून पर आ गयी रिपोर्ट समिति ने सीएम धामी को सौंपी

समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी 23 संस्तुतियां

मो० सलीम सैफ़ी की विशेष रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राज्य में भू - कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय - विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।

आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य व श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढौंडियाल व डी.एस.गर्ब्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू - कानून में संशोधन करेगी।

जुलाई 2021 में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी

मुख्यमंत्री धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रख कर विकास कार्य प्रभावित न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार - विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी।

सभी हितधारकों से सुझाव लेकर गहन विचार विमर्श कर 80 पृष्ठ में तैयार की रिपोर्ट

समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार - विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांग कर उनका परीक्षण भी किया।

राज्य में निवेश और रोजगार बढाने के साथ भूमि के दुरूपयोग को रोकने पर फोकस

समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है। समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है।

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

- वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि/औद्यानिक प्रयोजन न करके रिसोर्ट/ निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहें और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है।

समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाऐं। शासन से ही अनुमति का प्रावधान हो।

- वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमांचल प्रदेश की भाँति ही ये अनुमतियाँ, शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर, प्राप्त की जाएं।

उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता (Essentiality Certificate) के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

- केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल / रिसॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल/प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट आदि को ही Essentiality Certificate के आधार भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है।

- वर्तमान में, गैर कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन में S.D.M. धारा- 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा।परन्तु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग ना करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने/विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, यह भी शर्त में उल्लखित रहता है।

यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को ₹गैर कृषि₹ घोषित कर दिया जाता है, तो फिर यह धारा-167 के अंतर्गत राज्य सरकार में (उल्लंघन की स्थिति में) निहित नहीं की जा सकती है।अतः नई उपधारा जोड़ते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है।

- कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बिना अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद सकता है ।

समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिया जाए।

- राज्य सरकार 'भूमिहीन' को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन' की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा।

- भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई, उसका उललंघन रोकने के लिए एक जिला / मण्डल / शासन स्तर पर एक टास्क फ़ोर्स बनायीं जाए। ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके।

- सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइनबोर्ड लगाएं। - कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है तथा भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए Right of Way की व्यवस्था।

- विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो भूमि खरीदी जायेगी उसमें समूह ग व समूह 'घ' श्रेणीयो में स्थानीय लोगो को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यतानुसार वरीयता दी जाए।

- विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गयीं अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों/ संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो

- वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितयों में यह अवधि तीन वर्ष (2 + 1 = 3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- पारदर्शिता हेतु क्रय- विक्रय, भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया Online हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो।

- प्राथमिकता के आधार पर सिडकुल/ औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औद्योगिक प्लाट्स/ बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आबंटन औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाए।

- प्रदेश में वर्ष बन्दोबस्त हुआ है। जनहित/ राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।- भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद एवं शासन स्तर पर नियमित अंकन एवं इन अभिलेखों का रख-रखाव ।

- धार्मिक प्रयोजन हेतु कोई भूमि क्रय/ निर्माण किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए। - राज्य में भूमि व्यवस्था को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम/ नीति / भूमि सुधार कार्यक्रम चलायें जायें तो राज्य हितबद्ध पक्षकारों / राज्य की जनता से सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाएँ। - नदी - नालों, वन क्षेत्रों, चारागाहों, सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे /निर्माण / धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो। संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए।

मुसीबत में काम आते हैं ये 5 कार टूल्स क्या आपकी गाड़ी में भी हैं ?

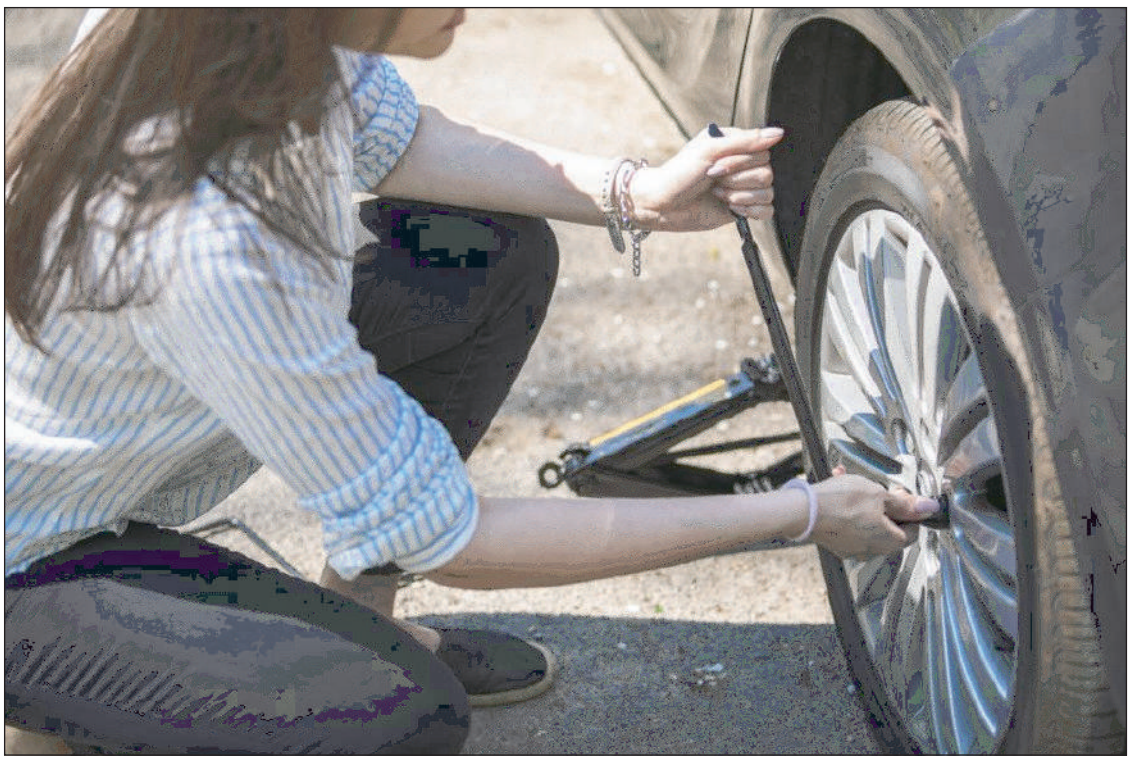

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कार कभी कभी सफर का मज़ा बिगाड़ देती है। अब सोचिये कि आप किसी हाइवे पर सरपट गाडी दौड़ा रहे हैं और अचानक कार किसी वजह से हाँथ खड़े कर दे तो क्या होगा ? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यात्रा के दौरान आपकी गाड़ी में खराबी आ गई और आप बीच सड़क में फंस गए तो कैसे बचेंगे ? यह खराबी भी इस तरह की थी, जिसे जरूरी टूल होने पर आप खुद ही ठीक कर सकते थे. इसलिए आज हम कुछ ऐसी आवश्यक चीजों के बारे में बताएंगे जिसे गाड़ी में रखना बहुत जरूरी है न सिर्फ गाड़ी को ठीक करने के लिए बल्कि खुद के लिए भी. वैसे तो ऐसे समय पर मैकेनिक को कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब खुद छोटी मोटी समस्या को ठीक कर सकते हैं तो मैकेनिक के आने का वेट क्यों करें. इसलिए गाड़ी से जुड़े टूल्स जरूर रखें.

हमारी संवाददाता महविश ने मेरठ के मशहूर कार ड्राइविंग एक्सपर्ट फ़िरोज़ आलम से जब इस आम समस्या पर बात की तो उनका भी यही कहना है कि एक बेहतरीन ड्राइवर होने के साथ साथ आपको हल्का फुल्का मेकेनिक भी होना चाहिए। क्योंकि सफर में आप जब अकेले होंगे तो ये हुनर मुश्किल वक़्त में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लिहाज़ा अपनी कार में ये 5 चीजें रखना कभी न भूलें ----

लाइफ हैमर

यह छोटा सा उपकरण आपात स्थिति में बहुत फायदेमंद होता है. हम चाहते हैं कि आप इसे कभी भी उपयोग न करें, लेकिन हम आपको इसे अपनी पास रखने की सलाह देते हैं क्योंकि यह आपातकालीन स्थितियों में आपकी मदद कर सकता है. यह ऐसी स्थिती में शीशा तोड़ने या सीट बेल्ट काटने में मदद करेगा, जब आप मुसिबत में फंस जाएंगे.

जंपर केबल

यदि आप फंस गए हैं तो जंपर केबल्स भी बहुत काम आ सकती है. हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पर इस बात पर नजर रखना भूल जाते हैं कि हमने पिछली बार अपनी कार की बैटरी कब बदली थी. हो सकता है कि आपकी कार की बैटरी कमजोर हो जाए और आपको इसके बारे में कोई जानकारी न हो. अगर आपके पास जंपर केबल हैं तो आप इसकी मदद से आसानी से अपनी कार स्टार्ट कर सकते हैं.

टायर इन्फ्लेटर

हम में से लगभग सभी अपनी कारों में स्पेयर टायर रखते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग नियमित रूप से टायर के प्रेशर की जांच करते हैं. क्या आपको याद है कि पिछली बार आपने अपनी कार के स्पेयर टायर की जांच कब की थी? टायर इन्फ्लेटर को अपनी गाड़ी में रख सकते हैं और समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

टॉर्च

कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी में बड़ी-बड़ी चीजें रख लेते हैं लेकिन छोटी चीजें भूल जाते हैं. और टॉर्च उनमें से एक है. हमें कार में हमेशा एक टॉर्च को रखना बहुत जरूरी है. कई बार रात के समय अगर कहीं फंस जाएं और गाड़ी स्टार्ट न हो तो उस समय टॉर्च की कमी बहुत खलती है.

फर्स्ट एड किट

आखिर में फर्स्ट एड किट, जो गाड़ी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है. हमेशा अपनी गाड़ी में एक फर्स्ट एड किड जरूर रखें, ताकि हर तरह की इमरजेंसी में ये काम आ सके. फर्स्ट एड किट में सबसे जरूरी सामान होता है- बैंडेज, डिस्पोजेबल ग्लव्स, टेप, थर्मामीटर, क्रीम या स्प्रे कीट, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेरासिटामोल आदि.

क्या आपने सोचा है कि सिम कार्ड एक कोने से क्यों काटे जाते हैं?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 6 सितम्बर , आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल न करता हो। आज चाहे 5 साल का छोटा बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा, आप सभी को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा होगा। इसके अलावा इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि लोग घंटों अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। इसी वजह से लोगों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। हालांकि, मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज उसमें लगा सिम कार्ड है।

सिम कार्ड के बिना, आपका फोन सिर्फ एक बॉक्स है। इसलिए फोन का इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड का होना अनिवार्य है। वैसे तो आपने अब तक कई कंपनियों के सिम कार्ड देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सिम कार्ड एक कोने से क्यों काटा जाता है या फिर इसके किसी एक कोने पर कट क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की अहम वजह के बारे में बताते हैं।

ऐसा नहीं है कि सिम कार्ड केवल अपने ही देश में किनारे से काटे जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह के सिम कार्ड बेचे जाते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में कई तरह की टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो बड़ी मात्रा में सिम कार्ड बनाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुराने जमाने में जो सिम कार्ड बनते थे वो साइड से नहीं कटे थे। उनका डिजाइन बहुत ही साधारण और आयताकार

आकार का हुआ करता था।

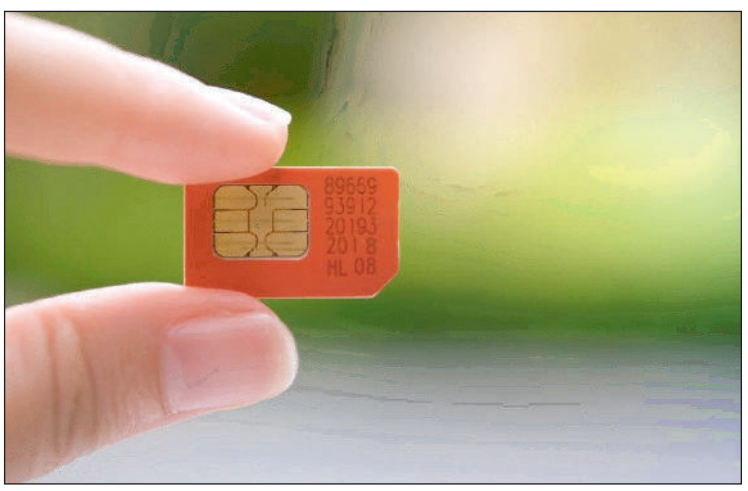

ऐसे में कई बार लोगों को यह समझने में काफी दिक्कत होती थी कि कौन सा सिम का सीधा हिस्सा है और कौन सा उल्टा हिस्सा। कुछ लोग सिम के सीधे और पीछे वाले हिस्से की पहचान नहीं कर पाने के कारण अपने मोबाइल फोन में सिम को उल्टा रख देते थे। इसके बाद नेटवर्क न मिलने पर सिम को दोबारा निकालने में काफी परेशानी हुई। यहां तक कि सिम की चिप भी कई बार खराब हो जाती थी।

ऐसे में लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम का साइज बदलने का फैसला किया। कंपनियों ने बदलाव करते हुए सिम कार्ड का एक किनारा काट दिया। इस कट के आने के बाद लोगों के लिए मोबाइल फोन में सिम कार्ड डालना और हटाना आसान हो गया क्योंकि वह कट मोबाइल फोन में भी सिम कार्ड के स्लॉट में दिखाया गया था। ऐसे में अब कोई भी आसानी से सिम कार्ड को फोन में लगा सकता है। लोगों को मिल रही इस सुविधा को देखकर तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने सिम कार्ड को नए कट डिजाइन के साथ बेचना शुरू कर दिया।

नितिन गडकरी ने प्रोटोटाइप अंग परिवहन का अनावरण किया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए मानव अंगों के ड्रोन परिवहन के भारत के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया क्योंकि उन्हें हवाई अड्डे से अस्पताल तक सड़क मार्ग से ले जाने का वर्तमान तरीका समय लेने वाला है। प्रोटोटाइप ड्रोन तकनीक का सह-निर्माण करने वाली एमजीएम हेल्थकेयर के निदेशक डॉ. प्रशांत राजगोपालन ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल अंगों वाले बॉक्स को 20 किमी की दूरी तक ले जाने के लिए किया जा सकता है। राजगोपालन ने कहा कि उनके अस्पताल ने अंगों को स्थानांतरित करने के लिए शहर की एक ड्रोन कंपनी के साथ गठजोड़ किया है, इसका उद्देश्य अंगों के अंतिम मील परिवहन में क्रांति लाना है। वस्तुतः अंगों के ड्रोन परिवहन का अनावरण करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा, ऱ्हम गति और निर्बाध अंग परिवहन के महत्व को समझते हैं, इसलिए हमें जल्द ही अंगों के परिवहन के रसद में नवाचार की आवश्यकता होगी। और ऐसा ही एक सुझाव ड्रोन का उपयोग है।ऱएमजीएम हेल्थकेयर को अनुसंधान और विकास टीम का हिस्सा बनने के लिए और कहा कि यह अंग परिवहन की समस्या को हल करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है।

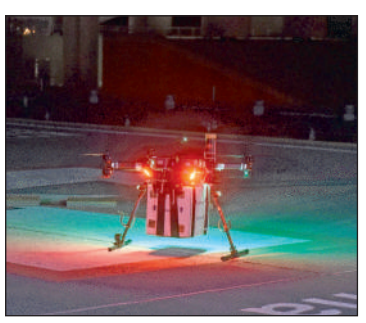

अंग परिवहन के लिए रसद के मुद्दे को बेहतर भूमि और हवाई संपर्क के माध्यम से हल किया जा सकता है, यह कहते हुए कि उनके मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहले ही उपाय शुरू कर दिए हैं।

'सल्ट क्रान्ति' के शहीद दिवस कार्यक्रम में सीएम ने की कई घोषणाएं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सल्ट , 6 सितम्बर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट, अल्मोड़ा में 5 सितंबर 'सल्ट क्रान्ति' के अवसर पर शहीद दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने खुमाड़, सल्ट में शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील परिसर सल्ट से खुमाड़, सल्ट में भव्य शहीद स्मारक बनाए जाने ,5 सितम्बर शहीद दिवस पर आयोजित मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी शहीद चूडामणि राजकीय इण्टर कालेज खुमाड़ मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाने की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री धामी ने शक्तिपीठ भीना देवी मन्दिर के सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण किए जाने, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औनेड़ी तराड का नव भवन निर्माण किए जाने, राजकीय पॉलिटेक्निक सल्ट में सिविल ट्रेड की स्वीकृति प्रदान किए जाने, राजकीय आदर्श विद्यालय देवायल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटाचामी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैकणा व राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेसड़ी का नव भवन निर्माण किए जाने, अल्प विकसित पर्यटक स्थल मल्ला गड़कोट, थल्माड एवं खटलगाँव का सौन्दर्यीकरण किए जाने, सल्ट के अति दुर्गम क्षेत्र भीताकोटखाल, मरचूला एंव तराड़ में ए.एन.एम. सेन्टर की स्वीकृति प्रदान किए जाने, राजकीय इण्टर कालेज नेलवालपाली का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी शहीद अम्बा दत्त जी के नाम किए जाने, तल्ला मानिला मन्दिर स्थित विशेष अतिथि गृह का निर्माण किए जाने, देघाट - चिन्तोली मोटर मार्ग का नाम बदलकर स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी शहीद हरिकृष्ण हीरामणि जी मोटर मार्ग लिए जाने की बात कही।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सितंबर 'सल्ट क्रान्ति' में शहीदों को भावमीनि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेजों से लोहा लेते समय खुमाड़ क्षेत्र के शहीद हुए स्व० श्री खीमानन्द एवं उनके सगे भाई स्व० श्री गंगाराम सहित स्व० श्री बहादुर सिंह एवं स्व० श्री चूड़ामणि ने क्षेत्र के साथ अपना नाम अमर किया है। उन्होंने कहा सल्ट के इन महान क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में

उत्तराखण्ड का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। सल्ट क्रांति- स्वाधीनता आन्दोलन का एक अविस्मरणीय अध्याय रहा है। सल्ट क्षेत्र में आजादी की लड़ाई की शुरुआत कुली बेगार आन्दोलन के तहत ब्रिटिश हुकुमत के दमनकारी फैसलों की प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। इस क्षेत्र की जनता ने एक स्वर में कुली बेगार न देने का संकल्प किया। उन्होंने कहा आजादी की लड़ाई में खासकर सल्ट क्रांति को संचालित करने में उत्तराखंड के शिक्षकों की अहम भूमिका रही थी। सन 1942 में महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो और 'करो या मरो' के नारे की सल्ट क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सल्टवासियों की इसी देशभक्तिपूर्ण शहादत के कारण गांधीजी ने इस क्षेत्र को कुमाऊँ की बारदोली कहा था।

शिक्षक दिवस के अवसर पर विनय शंकर पांडेय ने युवाओं को दिखाई नई दिशा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार 06 सितम्बर। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने सोमवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर बीएचईएल के सेक्टर-2 स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह/ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्ज्वलित कर तथा प्रतिष्ठित शिक्षाविद् डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुये उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुये कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि शिक्षकों के महत्व व योगदान को इसी से समझा जा सकता है कि जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तो उसके अभिभावक पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चे को उस स्कूल के सिपुर्द करते हुये पूरी तरह से निश्चिन्त हो जाते हैं। उन्होंने गुरू गोविन्द दोऊं खड़े कांके लागू पांय.....का उल्लेख करते हुये कहा कि शिक्षक का समाज में अपना अलग स्थान है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षकों का मुख्य रूप से ध्यान अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराने पर होता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराने के साथ ही, उनका जुड़ाव बच्चों के साथ निश्चित रूप से होना चाहिये। उन्होंने कहा कि शिक्षक का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त कर लेना ही नहीं होना चाहिये, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने ज्ञान में भी अभिवृद्धि करते रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि आज के समय में, पहले की अपेक्षा काफी परिवर्तन आ गया है इसलिये यह आवश्यक है कि समय-समय पर शिक्षकों के लिये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एडवांटिस्ट कोर्स चलते रहने चाहिये।

विनय शंकर पाण्डेय ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे कक्षा में कमजोर बच्चों का विशेष

ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे की नींव मजबूत होती है, तो वे धीरे-धीरे पढ़ाई के महत्व को समझते हुये, आगे की कक्षाओं में अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष शिव शंकर जायसवाल ने कहा कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी बना रहना चाहिये तथा अपना आकलन करते हुये निरन्तर ज्ञानवर्द्धन करते रहना चाहिये। इस मौके पर जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य के लिये अन्नु सिंह, संतोषी नेगी, चंद्रकांता, विकास कुमार सीमा रानी, जयकुमार, रंजीता देवी, पुष्पा पांडे,, भगत सिंह, अश्वनी कुमार, मोनिका कंवर, रविकुमार, सत्येंद्र गौथियाल, विवेक सैनी, राहुल कुमार, नीरू अग्रवाल, अमरीश गौतम, मोहनलाल, सुभाष त्यागी, अवधेश कुमार, जय कुमार कश्यप, मुकेश कुमार, सुषमा देवी, दीपा शर्मा, ए गुरूरानी, डॉ0 आर.के.चौहान, लाल सिंह, अनीता शर्मा, पंकज चौहान, हेमा भारद्वाज आदि शिक्षकों तथा क्रीड़ा एवं स्काउट गाइड को सार्टीफिकेट, प्रतीक चिह्न आदि भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी के0के0 गुप्ता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का सफल संचालन जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) शिव प्रसाद सेमवाल ने किया।

इस अवसर पर आई0ए0एस प्रशिक्षु आशीष मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) नरेश कुमार हल्दियानी, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेश कुमार चौहान, प्रभारी अभिलाषी जनपद शिक्षा विभाग हरिद्वार डॉ0 सन्तोष चमोला सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं : विधानसभा अध्यक्ष

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कोटद्वार 6 सितंबर। खेल जगत फाउंडेशन, उत्तराखंड और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटद्वार में देवभूमि खेल चेतना यात्रा का शुभारंभ किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम गाड़ीघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने खेल चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बता दें कि खेल जगत फाउंडेशन, उत्तराखंड और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में देवभूमि खेल चेतना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर से 25 मई को यात्रा का शुभारंभ किया गया था। यहां से यात्रा चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा होते हुए नैनीताल पहुंची। इसके बाद वापस उधम सिंह नगर जाकर यात्रा संपन्न हुई। वहीं गढ़वाल के विभिन्न जिलों के लिए खेल चेतना यात्रा का शुभारंभ सोमवार को कोटद्वार से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया।

खेल-जगत फाउंडेशन के संस्थापक रतन कुमार गुप्ता ने बताया कि गढ़वाल मंडल में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून जिलों में यात्रा भ्रमण करेगी। बताया कि यात्रा का मकसद बच्चों में खेल भावना का विकास करना है और खेलों के प्रति उनमें उत्साह भरना है। इस यात्रा के दौरान लोगों और युवाओं को खेल, पर्यावरण, लोक संस्कृति, पर्यटन, नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है।5 सितंबर को कोटद्वार स्पोर्ट्स स्टेडियम से यात्रा प्रारंभ होकर 17 सितंबर को देहरादून में संपन्न होगी

विधानसभा अध्यक्ष खंडूडी ने खेल और खिलाड़ी के हित में उत्तराखंड की संपूर्ण जनपदों में देवभूमि खेल चेतना यात्रा की सराहना की।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं का ऐतिहासिक प्रदर्शन बताता है कि राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है।जिस राज्य एवं देश ने खेल को महत्व दिया है वहीं राज्य एवं देश विश्व पटल पर भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा की खेल की इन गतिविधियों के माध्यम से खिलाड़ी भावना एवं प्रतियोगीता की भावना उत्पन्न होती है। प्रतियोगिता सभी को अपने जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और चुनौती और परिवर्तन की सूरत में डटकर मुकाबला करना सिखाती है।

इस अवसर पर रतन कुमार गुप्ता, सोवेंद्र सिंह, सुमित कुमार, पंकज जुगरान, वरिष्ठ खिलाड़ी धीरेंद्र कंडारी, स्टेडियम इंचार्ज संदीप कुमार डूकलान, सहायक प्रशिक्षक महेश्वर नेगी, श्याम सिंह डांगी, परवीन बिष्ट, दर्शनी रावत, अनीता बिष्ट, मान सिंह थापा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

उत्तराखंड की गीतिका आनन्द बनी 'मिसेज इंडिया गैलेक्सी गॉर्जियस 2022'

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून ,6 सितंबर ,उत्तराखंड की बेटी, हरिद्वार रोड देहरादून निवासी गीतिका आनंद और कैमब्रियन हॉल स्कूल की पूर्व छात्रा, ने नई दिल्ली में भारत के सबसे प्रमुख पेजेंट ₹मिसेज इंडिया गैलेक्सी₹ के ग्रैंड फिनाले में ₹मिसेज इंडिया गैलेक्सी गॉर्जियस 2022₹ का खिताब हासिल किया है। पूरे भारत से 30,000 आवेदकों में से 60 विवाहित महिलाओं को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया था। इस विशाल आयोजन में कई चमचमाती हस्तियों, अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेताओं की उपस्थिति देखी गई। गीतिका शो के निदेशक गगनदीप कपूर और निदेशक सह मुख्य सलाहकार गिन्नी कपूर ₹वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स₹ की आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें यह अवसर दिया। गीतिका ने कहा कि यह उनके पति राहुल आनंद, पुत्र आर्य आनंद के सहयोग और प्रयासों से ही संभव हो पाया है। उनके पिता सुधीर कुमार मित्तल और ससुर स्वर्गीय केवल कुमार आनंद जी (पूर्व अध्यक्ष- देहरादून खुखरान बिरादरी) ने उन्हें हमेशा जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। इस ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से, गीतिका का एकमात्र उद्देश्य डौशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ₹डीएमडी₹ के बारे में जागरूकता पैदा करना है जो युवा लड़कों को प्रभावित करने वाली एक आनुवंशिक बीमारी है। ऐसे बच्चों को पालने में माता-पिता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी इस उपलब्धि के माध्यम से सभी माता-पिता को प्रेरित और आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए।

12 सितंबर को जल संस्थान मुख्यालय पर कर्मचारी संगठन करेगा बड़ी सभा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार 6 सितंबर , उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन उत्तराखंड प्रदेश के रजिस्ट्रेशन संख्या 431 के बैनर तले रमेश बिंजोला संगठन के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्य संयोजक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पंतदीप हरिद्वार में बैठक का आयोजन किया गया 1 बैठक में कर्मचारियों की न्यायोचित मांग जैसे गोल्डन कार्ड पदोन्नति में शिथिलीकरण कर्मचारियों को एसीपी का लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4200 ग्रेड वेतन का लाभ डाउनग्रेड को तत्काल निरस्त करने आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया साथ ही उनके द्वारा 12 सितंबर 2022 को जल संस्थान मुख्यालय नेहरू कॉलोनी देहरादून में गेट मीटिंग एवं आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों से उपस्थिति का आवाहन किया गया है 1

बैठक में संगठन के मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी प्रदेश कोषाध्यक्ष लालसिंह रौतेला प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप मल्होत्रा मंडलीय कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी संयोजक धूम सिंह सोलंकी हरिद्वार शाखा के शाखा अध्यक्ष अशोक शाखा सचिव अमित कुमार संयोजक भारत सिंह रावत वरिष्ठ कर्मचारी साथी नरेंद्र राजपूत रघुवीर सिंह रावत शाखा हरिद्वार के मीडिया प्रभारी प्रवीण सैनी वरिष्ठ साथी नथी सिंह शिव सिंह बिष्ट श्यामा प्रसाद रमेश कुमार अबरार अली रुड़की शाखा के अध्यक्ष राजेश शर्मा सचिव संजय शर्मा संयोजक राजकुमार अग्रवाल संयोजक अनिल शर्मा संयोजक राजपाल सिंह संयोजक पंकज कुमार संयोजक सनी कुमार लाल बहादुर थापा संयोजक राहुल सौरव पवार आदि भारी संख्या में कर्मचारि उपस्थित थे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवभूमि के 2 शिक्षकों को किया सम्मानित

फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 6 सितंबर। उत्तराखंड के दो आइडियल टीचर्स को जब शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर में शिक्षा के क्षेत्र बेहतर योगदान देने वाले चुनिंदा शिक्षकों के साथ सम्मानित किया तो देवभूमि का भी सम्मान बढ़ा है। आपको बता दें कि हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं से कौस्तुभ जोशी को उनके शिक्षण कार्यों में बेहतरीन योगदान के लिए इस सम्मान हेतु चयन किया गया।

हर वर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है. हर साल इसमें विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता है. इस साल देशभर के तमाम शिक्षकों के साथ प्रदेश के 2 शिक्षकों का भी इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. शिक्षा दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विज्ञान भवन में किया गया जहाँ उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना के तीन तीन शिक्षक सम्मानित हुए हैं.

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा : राजीव नयन बहुगुणा उवाच

आटे को लीटर में मापने की राहुल व्याधि कोई नई और अजूबा बीमारी नहीं है. यह रोग, बुद्धि में हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं के विटामिन की कमी से उपजता है.

राहुल के पिता भी इसी भाषाई रक्ताल्पपता से पीड़ित थे . एक बार उनके पिता ने प्रधानमंत्री रहते, गाँव के किसी खलिहान में सूखती लाल मिर्ची को देख प्रति प्रश्न किया - जब लाल मिर्च सौ रूपये किलो और हरी मिर्च दस रूपये किलो बिकती है , तो लोग हरी मिर्च की बजाय लाल मिर्च ही क्यों नहीं उपजाते है?

दर असल राहुल गाँधी को हिंदी अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा नहीं आती है. अतः वह भारतीय समाज के जीवन व्याकरण से वंचित हैं.

वह अंग्रेजी में सोच कर हिंदी बोलते हैं.

मोदी जी को भी हिंदी नहीं आती. इसी लिए लवडेन भोज्यम कह कर अपनी खिल्ली उड़वाते हैं . लेकिन चूंकि मोदी जी गुजराती में पारंगत है, इसलिए घाघ हैं. वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, और उनके अंध भक्त उनकी गलती को सही सिद्ध करने पर तुल पड़ते हैं.

मेरी दृढ़ मान्यता है , कि जिस भारतीय को हिंदी अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा नहीं आती, वह मंद बुद्धि है.

अपनी पत्रकारिता की नौकरी में मैंने देखा कि देहात की किसी बड़ी घटना को कवर करने दिल्ली से अंग्रेजी के बड़े बड़े पत्रकार आते थे . जिस अंग्रेजी पत्रकार को हिंदी नहीं आती थी , वह ग्रामीण महिलाओं के ठेठ ढूंढाडी संवादों को नहीं समझ पाते थे, और टुकुर टुकुर देखा करते थे . तब मैं उन्हें हिंदी में ख़बर का मर्म समझाता था , और बदले में अपनी शाम का पूरा खर्चा उनसे उठवाता था.

हिंदी जानना आवश्यक नहीं. यदि आप बांग्ला, मराठी , तमिल अथवा पंजाबी में से कोई भी एक भारतीय भाषा जानते हैं , तो भारतीय समाज का मर्म जान जायेंगे.

भारतीय मूल के वही अंग्रेजी लेखक सफल सिद्ध हुए हैं, जिन्हे अंग्रेजी के अलावा बांग्ला, पंजाबी अथवा तमिल आती हो. यथा - रविंद्र नाथ टैगोर , आर के नारायणन या खुशवंत सिंह.

भारतीय भाषा न जानने वाले अंग्रेजी लेखक सतही, बल्कि दो कौड़ी के हैं. जैसे विद्या नेपाल और सलमान रशदी.

राहुल गाँधी की सरलता और राष्ट्र निष्ठा असंदिग्ध है .लेकिन भारत की आत्मा को आत्मसात करने के लिए उन्हें गिटर पिटर अंग्रेजी बोलने वाले दून स्कूल के भूतपूर्व बूढ़े छात्र छोकरों की बजाय देहाती राजनेताओं की संगत करनी होगी.

विकास कार्य ही मेरा लक्ष्य : रेखा आर्या

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सोमेश्वर(अल्मोड़ा) 6 सितम्बर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रमेला डूंगरी गांव में 24 मीटर पैदल स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्व में 2010 में आई आपदा में यहाँ पर जो पुल था वह बह गया था आज इस पुल का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द यह पुल बनकर अस्तित्व में आ जायेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होंगी.

उन्होंने बताया कि राज्य योजना के अंतर्गत इस पुल का निर्माण होगा जिसकी कुल लागत 132.20लाख रुपये है... वहीं साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित नैकाने पुल का भी शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पुल वर्ष 2013 में आई आपदा में बह गया था जिसका की आज विधिवत शिलान्यास किया गया है.उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर इन दोनों ही पुलों को जनता को समर्पित कर दिया जायेगा.ग्राम नैकाना में बन रहे पुल की कुल लागत 163.69 लाख है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने सम्बोधन में कहा की पुल के निर्माण को लेकर वह कई सालो से प्रयासरत थी लेकिन 2016 से पूर्व वह दूसरे दल में थी ऐसे में इस पुल के निर्माण में कई दिक्कते आयी लेकिन जब वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस पुल के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिली.उन्होंने कहा की यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेतृव में वह लगातार विकास के कार्यों को कर रही हैं.

विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा की चुनाव के वक्त विपक्ष द्वारा पुल को लेकर लगातार भ्रान्तियाँ फैलाई गई,विपक्ष कुकर में सिटी कब बजेगी का ताना मारते थे .उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा की जिस दिन पुल का लोकार्पण किया जायेगा उस दिन पुल के ऊपर ही कुकर में सिटी भी लगाएंगे. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने चुनाव में भारी मतों से जिताने को लेकर सभी क्षेत्र वासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा की सोमेश्वर की बेटी होने के नाते क्षेत्र के विकास के लिए वह हर पल तत्पर रहेंगी.

लोगों की समस्याओं का समाधान धरातल स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 6 सितम्बर , अधिकारी संवेदनशीलता से आम जनमानस की समस्याओं को निस्तारित करें। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे तक जनता की समस्याओं के निस्तारण के दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने यह निर्देश अफसरों को दिए हैं ।

सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण, भूमि कब्जा, भूमि खरीद-फरोख्त से संबंधित विवाद, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन से संबंधित समस्याएं, सामाजिक पेंशन, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, शस्त्र लाइसेंस निरस्त्रीकरण, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत, दाखिल खारिज, सीमांकन, सीवर का पानी की निकासी, सरकारी भूमि पर कब्जा हटवाने जैसी शिकायतें लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। देहरादून के अमृतकुंज मे स्ट्रीट लाइट्स से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम को इस पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। जनपद में पीएमजीएसवाई द्वारा सड़कों के कटान के दौरान मलबे के निस्तारण से संबंधित शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चैहान को कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सरखेत आपदा प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द सोलर लाइट लगवाने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। अधिकारी संवेदनशीलता तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। समस्त विभाग आपसी समन्वय तथा सहयोगात्मक कार्यशैली अपनाएं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्राम ब्लॉक तथा तहसील स्तरीय अधिकारी आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण कुशलता तथा अविलंब अपने स्तर पर करने का प्रयास करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो।

जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी डॉ शिव कुमार बरनवाल, के के मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चैहान, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपशिखा रावत संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे तथा समस्त उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े रहे।

बाप रे ! अब शौचालय पर लग गया GST, बजट देखकर करें इस्तेमाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 सितम्बर । हर शहर और सार्वजनिक स्थानों पर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते ही होंगे। कहीं 5 रूपये तो कहीं 10 रूपये का चार्ज देना पड़ता है जो जायज़ भी है। लेकिन केवल मूत्रालय का इस्तेमाल करने पर आपको सौ रूपये से ज्यादा चुकाना पड़े तो आप क्या कहेंगे ? हमारे देश में पब्लिक टॉयलेट्स की इस वक्त कम से कम शहरों में कमी नहीं है. रेलवे स्टेशन या किसी और पब्लिक प्लेस पर हम वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए 5-10 रुपये देते हैं. अगर कोई आपसे इसी सुविधा के लिए 50 रुपये भी मांग लेगा, तो यकीनन आप उसे मना करेंगे लेकिन आगरा में ब्रिटिश टूरिस्ट्स से टॉयलेट जैसी बेसिक चीज़ के इस्तेमाल के बदले 224 रुपये मांगे गए.... क्या आपक यकीन करेंगे ?

सैलानियों से टॉयलेट यूज़र करने के बदले लिए 224 रुपये

ये खबर जितनी सुनने में अजीब है, उतना ही अनोखा मामला भी है. दरअसल ब्रिटिश एम्बेसी से दो सैलानी आगरा पहुंचे थे. कैंट स्टेशन पर उन्हें वॉशरूम जाना था. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें इसके लिए लाउंज की फीस पर 12% का जीएसटी लगाने के बाद बिल सौंपा गया. दिलचस्प बात ये है कि इस पर 50 फीसदी की छूट भी दी गई थी और उनसे मिनिमम 112 रुपये की ज़रूरी फीस ही ली गई थी. चूंकि सैलानी 2 थे, ऐसे में उनका बिल 224 रुपये बना. इस बिल में कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी, फ्री वाईफाई और 2 घंटे तक लाउंज में रहने की भी सुविधा मौजूद थी. वो बात अलग है कि सैलानी सिर्फ टॉयलेट यूज़ करके वापस आ गए थे

ब्रिटेन से आए हुए दो सैलानियों ने आगरा रेलवे स्टेशन पर बने IRCTC Executive Lounge में सिर्फ टॉयलेट का इस्तेमाल किया था, जिसके बदले उन्हें सैकड़ों रुपये चुकाने पड़ गए. आखिर इन सैलानियों के लिए ये सुविधा इतनी महंगी क्यों पड़ गई? आप इसकी वजह सुनेंगे तो आपको और भी अजीब लगेगा क्योंकि इस पर 12 फीसदी का जीएसटी भी लगाया गया था... तो अगली बार जब आप पब्लिक टॉयलेट जाने की सोचे तो जेब ज़रूर चेक कर लें।

एक क्लिक पर मिलेगा जमीनों का रिकॉर्ड, इस सप्ताह शुरू होगा नक्शों का डिजिटलाइजेशन

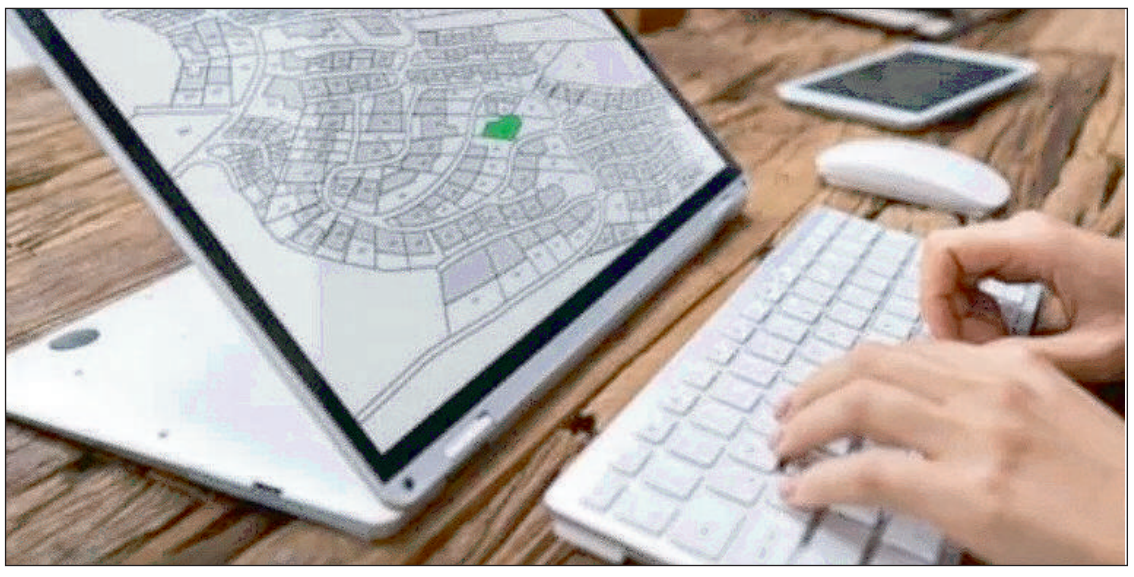

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेश में अल्मोड़ा और पौड़ी के बाद अब 11 अन्य जिलों के भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का काम शुरू होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। संभव है कि इस सप्ताह काम शुरू हो जाए। प्रदेश में आने वाले दिनों में जमीनों की रिकॉर्ड एक क्लिक पर मिल जाएगा। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड माडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के सजरा मानचित्र का जीआईएस बेस मैप तैयार किया जाएगा। इसमें सर्वे कराने के बाद नक्शों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। सभी जमीन को बाकायदा एक यूनिक नंबर दिया जाएगा।इन नंबर के जरिये आप दुनिया में कहीं भी बैठकर अपनी जमीन की स्थिति देख पाएंगे। संबंधित व्यक्ति के पास अपनी जमीन का वास्तविक डाटा बेस उपलब्ध होगा। इसके अलावा भूमि संपत्ति विवादों के दायरे को कम किया जा सकेगा और भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

411 राजस्व न्यायालय ऑनलाइन सचिव राजस्व चंद्रेश यादव ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की ओर से संचालित इस योजना के लिए सौ प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। प्रदेश में इस योजना को अगले दो साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सचिव राजस्व चंद्रेश यादव ने बताया कि प्रदेश में 411 राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें राजस्व शुल्क ऑनलाइन लिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

सात महीने से भटक रही थी महिला, केस दर्ज होने पर ली राहत की सांस, भैंस चोरी का था मामला

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

एक महिला को भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए साढ़े सात महीने तक संघर्ष करना पड़ा। सीएम के दरबार में जब इस मामले की शिकायत पहुंची तो उसके बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज हो पाई। 21 जनवरी 2022 को अर्जुनपुर क्षेत्र के हाथीखाल निवासी खष्टी देवी की गोशाला से दो भैंसें चोरी हो गईं।

अगले दिन महिला भैंस चोरी की शिकायत लेकर मंडी पुलिस चौकी पहुंची लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर वह अपनी शिकायत लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची लेकिन यहां भी उन्हें मंडी पुलिस चौकी जाने के लिए कहा गया। सात महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं की तो खष्टी देवी ने सीएम को प्रार्थनापत्र भेजा। सीएम कार्यालय से निर्देश आने के बाद महिला की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी एसटीएफ का ऑपरेशन शुरू

■ ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती परीक्षा में दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

साइबर थाना देहरादून पर वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा को लेकर दिनांक 4-9-22 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी परतें भी एसटीएफ ने खंगालनी शुरू कर दी है । इस क्रम में आज एसटीएफ द्वारा ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी गई है । अभ्यर्थियों से प्रारंभिक पूछताछ से स्पष्ट हो गया है कि इस भर्ती परीक्षा के दौरान सुनियोजित तरीके से एक गिरोह द्वारा इस परीक्षा में अनुचित साधनों से अभ्यर्थियों को परीक्षा में नकल कराई गई है।

एसटीएफ द्वारा इस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है।

1..प्रशांत कुमार पुत्र बाबूराम उम्र 28 निवासी ग्राम खानपुर, हरिद्वार2..रविंद्र सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह उम्र 27 निवासी वार्ड नं 11, लक्सरी, थाना लक्सर, हरिद्वार।

संपादकीय

बढ़ती सामुद्रिक शक्ति

युद्धपोत विक्रांत का नौसैनिक बेड़े में शामिल होना गौरवशाली परिघटना है. इसके साथ ही भारत उन कुछ देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे युद्धपोत बनाने की क्षमता है. पूर्ववर्ती युद्धपोत विक्रांत से लगभग तीन गुना बड़े इस जहाज की रूप-रेखा भारतीय है तथा देश में निर्मित यह सबसे बड़ा युद्धपोत भी है. इस अत्याधुनिक युद्धपोत के निर्माण के पीछे ढाई दशकों का परिश्रम है. एक ओर सरकार का प्रयास है कि सैन्य क्षमता के विस्तार के लिए विदेशी सहयोग और खरीद पर निर्भरता कम हो तथा दूसरी ओर थल, वायु और समुद्र में हमारी शक्ति बढ़े. हिंद-प्रशांत क्षेत्र कई कारकों की वजह से एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र बन गया है, जिसमें तमाम शक्तिशाली देशों की गहरी रूचि है. इस परिदृश्य में युद्धपोत विक्रांत का आना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है. उल्लेखनीय है कि कुछ समय से चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी बढ़ा है तथा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत है. उल्लेखनीय है कि चीन के दो बड़े युद्धपोत सक्रिय हैं तथा एक-दो वर्षों में तीसरा जहाज भी नौसैनिक बेड़े में शामिल हो सकता है. भारत के पास विक्रमादित्य युद्धपोत भी है, जो रूस से लिया गया है. भारतीय नौसेना ने तीसरे युद्धपोत की आवश्यकता को रेखांकित किया है. जानकारों का आकलन है कि विक्रांत के निर्माण अनुभव के कारण अगला युद्धपोत बनाने में कम समय लगेगा तथा उसकी लागत भी कम हो सकती है. तीसरे युद्धपोत की जरूरत इसलिए भी है कि अगर कोई जहाज मरम्मत के लिए खड़ा है, तो सैन्य क्षमता में कुछ समय के लिए कमी आ सकती है. लड़ाकू जहाज ढोने तथा बड़ी संख्या में अन्य सैन्य साजो-सामान की क्षमता से लैस बड़े युद्धपोत केवल सामुद्रिक सीमाओं की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में बहुत दूर तक गश्त लगाकर शत्रुओं की हरकतों पर नजर भी रखते हैं तथा मालवाहक जहाजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं. ऐसे में अगर हमारे पास तीसरा युद्धपोत आ जाता है, तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में एक-एक जहाज की तैनाती की जा सकती है, यदि तीसरा पोत खड़ा हो. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने तथा अन्य देशों को साजो-सामान निर्यात करने के उद्देश्य से हो रहे प्रयासों के कारण रक्षा उद्योग का विस्तार भी हो रहा है तथा आयात पर हमारी निर्भरता भी कम हो रही है. आज हम युद्धपोत निर्माण के साथ डीजल व परमाणु शक्ति से चालित पनडुब्बियां तथा हल्के लड़ाकू हवाई जहाज देश में ही बनाने की क्षमता रखते हैं. नवागत युद्धपोत विक्रांत भारतीय सैन्य शक्ति के साथ-साथ हमारी आत्मनिर्भरता का भी गौरव प्रतीक है.

5000 कारें चुराने वाला देश का सबसे बड़ा कार चोर निकला रिक्शावाला

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 6 सितम्बर , दिल्ली पुलिस को देश का सबसे बड़ा कार चोर हाथ लगा है। ये वो शातिर चोर है जो अब तक एक दो नहीं पांच हजार से अधिक कारों की चोरी कर चुका है। अभियुक्त पर हत्या, आर्म्स एक्ट और तस्करी के मामले में कई थानों में केस दर्ज हैं। अभियुक्त 27 साल से अपराध की दुनिया में एक्टिव है।

4552 कारों की चोरी करने की बात की कबूल

अपराध की दुनिया में अनिल चौहान एक कुख्यात नाम है। देश वो सबसे बड़ा कार चोर है। अनिल कुल 4552 कारों की चोरी करने की बात खुल कबूल कर चुका है। उसका नेटवर्ट दिल्ली से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों, जम्मू कश्मीर और नेपाल तक फैला था।

2 दशक पहले ऑटो रिक्शा चलाता था अनिल चौहान

अनिल चौहान ने दो दशक पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। इससे पहले वो 1990 में दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था। अनिल दिल्ली के खानपुर इलाके में रहता है। ऑटो रिक्शा चलाना छोड़ने बाद वो कार चोरी करने लगा। जिसके बाद उसने धीरे-धीरे चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बना ली।कार चोरी के अलाव अनिल के खिलाफ कार चोरी, आर्म्स एक्ट, तस्करी समेत कई अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे असम से गिरफ्तार किया। शुरुआती दौर में अनिल ने सबसे अधिक मारुति 800 कारों की चोरी की थी। जो जम्मू कश्मीर ,नेपाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में बेंची गई थी।

साल 2015 में असम पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अनिल चौहान दिल्ली, महाराष्ट्र और असम समेत देश के कई राज्यों से साढ़े चार हजार से ज्यादा कारें चुराने का आरोप है। अनिल को सात साल पहले साल 2015 में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था दिल्ली, महाराष्ट्र और असम समेत अन्य कई राज्यों कार चोरी का। अनिल के खिलाफ कार चोरी समेत अन्य कई आपराधिक मामले में कुल साढ़े तीन हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए। ये सभी केस दिल्ली, असम समते अन्य कई राज्यों में दर्ज किए गए।

आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में पुनर्निर्माण कार्यों में लाएं तेज़ी : गणेश जोशी

न्यूज वायरस नेटवर्क

देहरादून 06 सितंबर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सरखेत में भीषण आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों की ली जानकारी . अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सरखेत, चमरोली, कायरा, सिला आदि गांवों में बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू हो गई है। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छमरोली, घन्तु का शैरा गांव के सड़क मार्ग को दो दिन के अंदर सुचारू करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने सरखेत के आपदा प्रभावितों के विस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही जमीन तलाशकार प्रभावितों को विस्थापन किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता एसके गर्ग, ईई डीसी नौटियाल, सिंचाई के ईई डीसी उनियाल, जलनिगम के ईई सुमित कश्यप, विद्युत विभाग के ईई राकेश कुमार, अनुज कौशल सहित कई अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद एमएस धोनी के अलावा किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया : विराट कोहली

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

एशिया कप में फॉर्म में वापिस आते दिखे विराट कोहली। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं जबकि यह उनके लिए लंबा और कठिन दौर रहा है, उन्होंने घोषणा की कि उन्हें केवल पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से ही वास्तविक समर्थन मिला है।ह्मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो केवल एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने खेला, उसने मुझे मैसेज किया। वो हैं एमएस धोनी। बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर है। लोग टीवी पर सुझाव देते हैं। लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जिन लोगों के पास मेरा नंबर था, उन्होंने मैसेज नहीं किया।'इस चरण ने उन्हें लोगों के माध्यम से देखने में भी मदद की है।

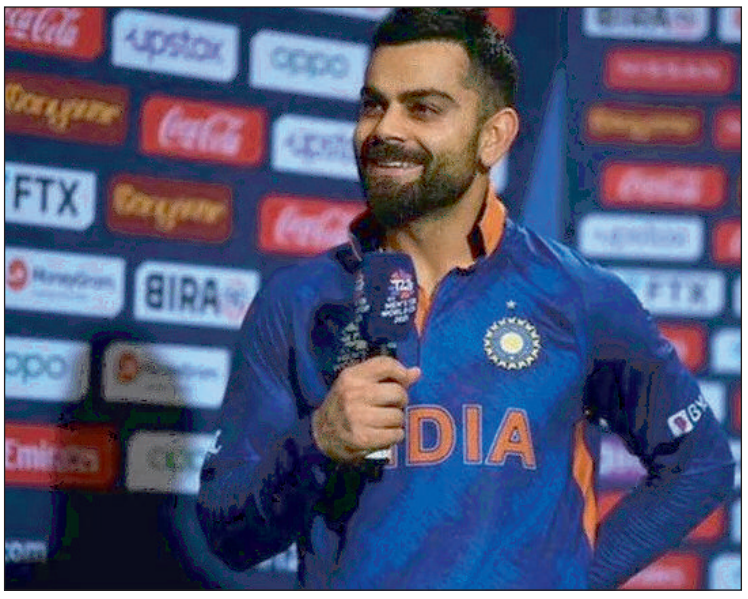

"किसी तरह, मैं अपना जीवन ईमानदारी के साथ जीता हूँ और मैं इन चीजों के माध्यम से देख सकता हूँ। मैं यह नहीं कहूंगा कि ये बातें मुझे परेशान नहीं करतीं, लेकिन आप सच देखते हैं। जब आप इतनी देर तक ईमानदारी से खेलते हैं, तो सर्वशक्तिमान आपको पुरस्कृत करता है। जब तक मैं खेलने के लायक हूं, मैं इसी तरह खेलता रहूंगा।"मीडिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कोहली का समर्थन किया है, लेकिन उनका मानना है कि यह बहुत कम मायने रखता है।

मैं केवल एक ही बात कहूंगा। अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, तो व्यक्तिगत रूप से कहूंगा। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं। अगर आप उन सुझावों को दुनिया के सामने देते हैं, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर यह मेरी मदद करने वाला है, तो आपको आमने-सामने बात करनी चाहिए। अगर वह वास्तव में चाहते हैं कि मैं अच्छा करूंउनके अनुसार, पिछले आठ महीनों के दौरान उनके और धोनी के बीच सुरक्षा की भावना सबसे अलग थी। ह्जब आप किसी के लिए सम्मान करते हैं और यह वास्तविक है, तो ऐसा लगता है क्योंकि दोनों तरफ सुरक्षा की भावना है। न तो उसे मुझसे कुछ चाहिए और न ही मुझे उससे कुछ चाहिए। मैं उससे कभी भी असुरक्षित नहीं था और न ही वह था, "कोहली ने सीधे चेहरे के साथ जोड़ा।

भाजपा पर बरसी कांग्रेस, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाजपा ले रही है कांग्रेस की आड़ : दसौनी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान लगाए गए इल्जामों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दसौनी ने कहा की भाजपा प्रवक्ता को कांग्रेस के घोटाले गिनाने का बहुत शौक चढ़ा है तो उन्हें कम से कम अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था।

दसोनी ने कहा राज्य गठन के बाद ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब होती है। दसोनी ने सिलसिलेवार तरीके से पूछा की स्टूरजिया हाउसिंग घोटाला किसकी देन था? सिडकुल घोटाला की सरकार की देन था ? 56 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तमाम शराब माफियाओं को देने के बाद किसके दबाव में रातों-रात एनओसी रद्द कर दी गई? 2010 का महाकुंभ घोटाला जिसकी वजह से रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी वह किस पार्टी की सरकार थी?बाद में

केंद्र का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी किस वजह से निशंक जी से ले लिया गया? और तो और दसोनी ने कहा कि हम 2017 से सुनते आ रहे हैं कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है फिर ऐसे में 2018 की 917 लेक्चरर पद पर भर्ती हो या फिर 2019 की वन दरोगा भर्ती में हुआ घोटाला या ताजा बात करें तो 2021-22 में हुए यूके ट्रिपल एससी की भर्तीयों में हुआ भ्रष्टाचार सुरेश जोशी बताएं कि यह सभी घपले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए तो किसकी सरकार थी ?गरिमा ने कहा कि सुरेश जोशी बताएं कि पिछले 6 सालों से राज्य में प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है ऐसे में क्या कारण है कि कांग्रेस के इतने घोटालों का संज्ञान होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक किसी पर भी जांच नहीं बैठाई इसका मतलब यह समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के तथाकथित घोटालों को अपना संरक्षण दे रही है? क्या सुरेश जोशी अपनी ही सरकार को निकम्मा साबित करना चाहते हैं? द सोनी ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आज जब चौतरफा घिर गई है ऐसे में अपनी सरकारों में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस की आड़ लेने का काम कर रही है।

मंत्री सुबोध उनियाल ने ली सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की तैयारियों पर बैठक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

टिहरी 6 सितम्बर, गढ़वाल का सुप्रसिद्ध नरेन्द्रनगर में आयोजित होने वाला 46 वाँ सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के आयोजन को लेकर नगर पालिका परिषद् नरेन्द्रनगर के टाउन हॉल में वन एवं तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं निर्वाचन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार सुबोध उनियाल की अध्यक्षता तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। 8 दिवसीय इस मेले का उदघाटन 26 सितम्बर, को होगा, जबकि समापन 3 अक्टूबर, 2022 को किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

मंत्री उनियाल ने कहा कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नरेन्द्रनगर में आगामी शरदकालीन नवरात्रों के शुभ अवसर पर 46

वाँ सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां कुजांपुरी पर्यटन एवम् विकास मेला उत्तराखण्ड का सुप्रसिद्ध व काफी पुराना मेला है। यह मेला धार्मिक मेले के रूप में प्रारम्भ हुआ था, जो काफी वर्षो से पर्यटन के क्षेत्र में भी इस मेले ने अपना स्थान बनाया है। उन्होंने आश्वासन दिया गया कि किसी भी स्तर पर भी माँ कुंजापुरी के इस मेले हेतु धन की कोई कमी आड़े नही आने दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिला इस मेले में जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का पहला मेला है जिसकी निरंतरता आज भी बनी हुई है मेले का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही खेलों को बढ़ावा देना तथा यहां की स्थानीय संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के साथ-साथ विकास की निरंतरता को भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मेले की गुणवत्ता पर ध्यान रखना जरूरी है सभी को सकारात्मक सोच एवं रचनात्मकता के साथ अपना योगदान देना आवश्यक है। साथ ही मेले में जन कल्याणकारी योजनाओं के विभागीय प्रदर्शनी/ स्टॉल लगाकर लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियों की बैठक तीन चार दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें। खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित समितियां पहले ही अपनी तैयारियां पूर्ण कर ले। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागों की योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाना सुनिश्चित करेंगे। पार्किंग व्यवस्था एसडीएम सीओ औऱ पीडब्ल्यूडी देखना सुनिश्चित करेंगे ईओ नगरपालिका साफ-सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तथा सफाई हेतु समय निर्धारित कर सफाई करवाएंगे। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति, जल संस्थान द्वारा पेयजल व पानी निकासी व्यवस्था, खाद्य अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों को खुले में ना रखने संबंधी व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंबुलेंस एवं स्वास्थ्य टीम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मेले का लोगो बनाने का भी सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष मां कुंजापुरी मेले को और बेहतर तरीके से किए जाने का प्रयास किया जाएगा और इसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा